

>

Title: Need to ensure supply of adequate quantity of fertilizers in Madhya Pradesh.

श्री रakesh सिंह (जबलपुर): सभापति महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हम सभी अरसे से ऐसा मानते चले आ रहे हैं। इसलिए हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, उसमें कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है, इसे भी सब मानते हैं। लगभग 70 प्रतिशत के आसपास आबादी इस व्यवसाय और क्षेत्र से जुड़ी है। मौसम की अनुकूलता हो या प्रतिफलता, दोनों का ही सीधा असर किसान के ऊपर होता है। जब उस पर प्रतिफलता होती है, तो उससे उसके कृषि के उत्पादन पर असर होता है। हमें इसे मानकर चलना चाहिए कि यह किसान की बेबसी है। इसका कोई हल आज हम वैज्ञानिक रूप से भी नहीं निकाल सके हैं। इसलिए हम यह मानते हैं कि राज्यों में किस दल की सरकार है, इसके आधार पर किसी राज्य के किसानों के साथ केन्द्र को भेदभाव नहीं करना चाहिए। पूर्व में इस देश में जो कृषि की नीति रही है, वह सही रही है या गलत रही है, यह चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन उसका दुष्परिणाम यह है कि आज कृषि क्षेत्र में पूर्णतः निर्भरता रासायनिक खाद के ऊपर हो चुकी है। मौसम अनुकूल है, सिंचाई के साधन हैं, बिजली है, इन सबके बावजूद भी अगर रासायनिक खाद नहीं है तो उत्पादन में उसका असर निश्चित रूप से होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में हमारी डीएपी की 1.80 लाख मीट्रिक टन और एनपीके की 1.75 लाख मीट्रिक टन की आवश्यकता थी। इसकी मांग भी केन्द्र में आई। माननीय मुख्य मंत्री स्वयं दिल्ली आए थे। वे मंत्री जी से मिले। उन्होंने माननीय प्रधान मंत्री जी को पत्र भेजा। लेकिन दुर्भाग्य से हमें डीएपी में मात्र 1.45 लाख मीट्रिक टन और एनपीके में 1.12 लाख मीट्रिक टन का आवंटन हुआ। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक ओर किसान खाद की कमी का सामना कर रहा है। केन्द्र सरकार ने रासायनिक खाद की कीमतें बढ़ा दीं। जहां उसे खाद नहीं मिल रही है वहां खाद की कालाबाजारी बढ़ रही है। महंगी कीमत देने के बावजूद भी किसान को खाद उपलब्ध नहीं हो रही है।

मैं पिछले दिनों अपने संसदीय क्षेत्र में था। मैंने जो स्थिति देखी, किसान खून के आंसू रो रहा है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जिस तरह आज हमारी आबादी बढ़ रही है, अगर हमें भविष्य की चुनौतियों का सामना करना है, यदि कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाना है, तो खेती फायदे का धंधा बने, हमें इसका प्रयास करना होगा। मध्य प्रदेश की सरकार और माननीय मुख्य मंत्री जी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने एक प्रतिशत की ब्याज दर पर किसानों को ऋण देने का फैसला करके इस दिशा में कदम भी आगे बढ़ाया है। लेकिन मात्र इतना पर्याप्त नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर इसमें केन्द्र सरकार भी अपने हिस्से की सहभागिता देगी, तो निश्चय ही खेती लाभ का सौदा बनेगी। मुझे आज ही जानकारी मिली कि माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को जब इस बात की जानकारी मिली, तो...(व्यवधान)

सभापति जी, मैं अपनी बात सामाप्त कर रहा हूँ। उन्होंने इसमें हस्तक्षेप किया और केन्द्र सरकार के माननीय मंत्रीगणों से इस बारे में चर्चा की। उनको यह आश्वासन मिला है कि जल्दी ही खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी जायेगी। ...(व्यवधान) मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से यही आग्रह है कि उन्हें आश्वासन दिया गया है, तो सरकार तत्काल खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करने का कष्ट करे। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : You can associate and send your slips.

*(Interruptions) â€!**

श्री रakesh सिंह : सभापति महोदय, आसन की तरफ से यह निर्देश सरकार को जाना चाहिए। ...(व्यवधान) मेरा आपके माध्यम से इतना ही आग्रह है कि केन्द्र सरकार खाद की आपूर्ति को सुनिश्चित कराने का काम करे। ...(व्यवधान) आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except Dr. Rajan Sushant's speech.

*(Interruptions) â€! **

MR. CHAIRMAN: Everybody is speaking about *kisans*.

Shrimati Jyoti Dhurve,

Shri Virendra Kumar and

Shri Hansraj Ahir are allowed to associate with the matter raised by Shri Rakesh Singh.